



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2018/चैत्र 20, 1940

No. 128]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2018/CHAITRA 20, 1940

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

नोडल एजेंसी के रूप में पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड और समूहक के रूप में पीटीसी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से मध्यावधि के लिए पायलट योजना के अंतर्गत विद्युत की खरीद के लिए दिशा-निर्देश।

सं.23/17/2013-आरएंडआर(खंड-IV)—जबकि केंद्र सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 ("**अधिनियम**") के प्रावधानों के अनुसार विद्युत के उत्पादन की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए एक सक्षम नीति और विनियामक वातावरण सृजित करने में लगी हुई हैं।

जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विद्युत विनियामक आयोगों और वितरण लाइसेंसियों के लिए प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्युत की खरीद में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन देना आवश्यक होता है।

जबकि केंद्र सरकार ने उत्पादन कंपनियों, जिनके पास कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है और जो विद्युत क्रय करार किए बिना तथा पहले से ही चालू हैं, से (मध्यावधि के अंतर्गत शामिल) 3 (तीन) वर्षों के लिए 2,500 मेगावाट विद्युत की खरीद को सुविधाजनक बनाने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित योजना में नोडल एजेंसी के रूप में पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत की खरीद की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) और वितरण लाइसेंसी (लाइसेंसियों) के बीच विद्युत की खरीद और आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्य से समूहक के रूप में कार्य करेगा। समूहक सफल बोलीदाताओं के साथ विद्युत की खरीद के लिए करार एवं साथ ही वितरण लाइसेंसी (लाइसेंसियों) के साथ बैक-टू-बैक विद्युत आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर करेगा। यह योजना बाद में "**पायलट योजना**" के रूप में संदर्भित की जाती है।

जबकि केंद्र सरकार ने दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के अपने पत्र सं. 23/17/2013-आरएंडआर(खंड-IV) में न्यूनतम प्रशुल्क के आधार पर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म (दीप ई-बिलिडिंग पोर्टल) के माध्यम से खुली प्रक्रिया तथा पारदर्शी प्रतिस्पर्द्धा बोली के माध्यम से विद्युत उत्पादकों से विद्युत की खरीद के लिए नोडल एजेंसी द्वारा अपनाए जाने के लिए बोली दस्तावेज जारी किए हैं जिनमें (i) योग्यता के लिए मॉडल पायलट अनुरोध (द "**एमपीआरएफन्यू**") और प्रस्ताव के लिए मॉडल पायलट प्रस्ताव (द "**एमपीआरएफपी**") दोनों को शामिल करते हुए मानक बोली दस्तावेज के रूप में एकल दस्तावेज; (ii) विद्युत की खरीद के लिए मॉडल पायलट करार (द "**एमपीएपीपी**") और (iii) मॉडल पायलट विद्युत आपूर्ति करार (द "**एमपीपीएसए**") (सामूहिक रूप से "**मॉडल पायलट बोली दस्तावेज**") शामिल हैं। ई-बिलिडिंग

पोर्टल के लिए लिंक www.mstcecommerce.com और विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट (www.powermin.nic.in) और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (www.pfcclindia.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाएगा।

अब, इसलिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा नोडल एजेंसी के रूप में पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड और समूहक के रूप में पीटीसी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से पायलट स्कीम के अंतर्गत विद्युत की खरीद के लिए दिशा-निर्देश ("दिशा-निर्देश") अधिसूचित करती है।

ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे-

1. मॉडल पायलट बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट निबंधन और शर्तें इन दिशा-निर्देशों का भाग होंगी और उन्हें संदर्भ द्वारा उसी रूप में संदर्भित करना होगा।
2. इन दिशा-निर्देशों का उपयोग केवल उन परियोजनाओं तक सीमित होगा जिससे 3 (तीन) साल के लिए विद्युत खरीद करार के अनुसार विद्युत की खरीद की जाएगी।
3. विद्युत की खरीद के लिए करार के उद्देश्य से प्रशुल्क इस प्रकार शामिल होगा: (i) रु.0.01 (एक पैसा मात्र)/केडब्ल्यूएच निर्धारित प्रभार और (ii) परिवर्ती प्रभार जोकि मानक बोली दस्तावेज के अनुसरण में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत की जाएगी।
4. विद्युत आपूर्ति करार के उद्देश्य से प्रशुल्क इस प्रकार शामिल होगा: (i) विद्युत की खरीद के लिए करार के अंतर्गत प्रशुल्क और (ii) ट्रेडिंग मार्जिन। ट्रेडिंग मार्जिन इस पायलट योजना के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
5. विद्युत की खरीद और विद्युत आपूर्ति करार के उद्देश्य से दिशा-निर्देशों के आधार पर दीप ई-बोली के माध्यम से निर्धारित प्रशुल्क अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुरूप उपयुक्त आयोग द्वारा अपनाए जाएंगे।
6. सभी बोलीदाता पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) के इस बोली दस्तावेज के अंतर्गत रु.8000 प्रति मेगावाट की अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने से ई-बोली इवेंट्स के प्रतिभागी हो जाएंगे। बोली प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल सफल बोलीदाताओं को प्रत्येक बोलीदाता को आवंटित मात्रा के लिए इन प्रभारों को देना होगा। शेष राशि पीएफसीसीएल द्वारा सात कार्य दिवसों के बीच बिना किसी ब्याज के लौटाया जाएगा। गैर चयनित बोलीदाता (बोलीदाताओं) द्वारा जमा किया गया शुल्क भी कार्य के पूरा होने पर बिना किसी ब्याज के सात कार्य दिवसों में पीएफसीसीएल द्वारा वापिस किया जाएगा।
7. मॉडल पायलट बोली दस्तावेजों में कोई भी विचलन नोडल एजेंसी, समूहक अथवा वितरण लाइसेंसियों द्वारा केवल उपयुक्त आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा।

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 10th April, 2018

Guidelines for Procurement of Power under Pilot Scheme for medium term through PFC Consulting Limited as Nodal Agency and PTC India Limited as Aggregator

No. 23/17/2013-R&R(Vol-IV).—Whereas, the Central Government is engaged in creating an enabling policy and regulatory environment for the orderly growth of generation of electricity in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003 (the "Act");

Whereas, it is incumbent upon the Central Government, State Governments, Electricity Regulatory Commissions and the distribution licensees to promote competition in the procurement of electricity through competitive and transparent processes.

Whereas, the Central Government has decided to facilitate procurement of 2500 MW power for 3 (three) years(covered under medium term) from the generating companies having coal based Power Plants which are already commissioned and without having a power purchase agreement. The proposed scheme envisages procurement of Power through competitive bidding process to be conducted by PFC Consulting Limited, as Nodal Agency. Further, in order to facilitate the procurement and supply of power between the Successful Bidder(s) and Distribution Licensee(s), PTC India Limited will act as the Aggregator for the purpose of these Guidelines. The Aggregator will sign an Agreement for

Procurement of Power with the Successful Bidder(s) and back to back Power Supply Agreement with the Distribution Licensee(s). The scheme is hereinafter referred to as the **“Pilot Scheme”**.

Whereas, The Central Government has, therefore vide its letter No. 23/17/2013- R&R (Vol-IV) dated 6th April 2018 issued bidding documents comprising of (i) a single document as the “Standard Bidding Document” comprising both the Model Pilot Request for Qualification (the “MPRFQ”) and the Model Pilot Request for Proposal (the “MPRFP”); (ii) the Model Pilot Agreement for Procurement of Power (the “MPAPP”); and (iii) the Model Pilot Power Supply Agreement (the “MPPSA”) (collectively, the “Model Pilot Bidding Documents”) to be adopted by the Nodal Agency for procurement of power from the power producers through a process of open and transparent competitive bidding through an electronic platform (DEEP e-Bidding Portal) based on offer of the lowest tariff. The link for the e-Bidding Portal shall be made available at www.mstcecommerce.com, and shall also be available on the website of Ministry of Power (www.powermin.nic.in) and PFC Consulting Limited (www.pfcclindia.com).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 63 of the Electricity Act, 2003, the Central Government hereby notifies the **‘Guidelines for Procurement of Power under Pilot Scheme for medium term through PFC Consulting Limited as Nodal Agency and PTC India Limited as Aggregator’ (the “Guidelines”)**.

These Guidelines shall come into effect from the date of publication in the official gazette subject to the following terms and conditions:

1. The terms and conditions specified in the Model Pilot Bidding Documents referred to hereinabove shall, by reference, form part of these Guidelines and shall be treated as such.
2. The application of these Guidelines shall be restricted to projects from which power is procured in accordance with an Agreement for Procurement of Power for a period of 3 (three) years.
3. For the purpose of the Agreement for Procurement of Power, the tariff shall comprise of (i) a Fixed Charge of Rs. 0.01 (One Paisa only)/ kWh and (ii) a Variable Charge, to be quoted by the Bidders in accordance with the Standard Bidding Document.
4. For the purpose of the Power Supply Agreement, the tariff shall comprise of (i) the tariff under the Agreement for Procurement of Power; and (ii) a trading margin. The trading margin shall be as approved by the Appropriate Commission for this Pilot Scheme.
5. The tariff determined through the DEEP e-Bidding process based on these Guidelines for the purpose of Agreement for Procurement of Power and Power Supply Agreement shall be adopted by the Appropriate Commission in pursuance of the provisions of Section 63 of the Act.
6. All the Bidders would be able to participate in the e-Bidding events on making payment of the requisite fees of Rs. 8000 (Rupees Eight Thousand) per MW for the total capacity sought under this Bidding Document to PFC Consulting Limited (PFCCL). After the completion of the bidding process, only successful Bidder(s) will have to pay these charges for the quantum allocated to each bidder. The balance amount will be refunded by PFCCL within seven (7) working days without any interest. The fee deposited by non-selected Bidder(s) will also be refunded by PFCCL within seven (7) working days of completion of the event without any interest.
7. Any deviation from the Model Pilot Bidding Documents shall be made by the Nodal Agency, Aggregator or Distribution Licensees only with the prior approval of the Appropriate Commission.

GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer